

अनुक्रमणिका

क्र. सं.	टॉपिक का नाम
1.	राज उन्नति की चतुर्थ बैठक : जयपुर
2.	राजस्थान में कॉपियों की AI आधारित जाँच
3.	IIT जोधपुर द्वारा विकसित स्मार्ट 'थेरानोस्टिक' प्लेटफॉर्म
4.	न्यूज़ इन शॉर्ट्स 1. अखिल भारतीय शूटिंगबॉल प्रतियोगिता - 2026 2. चर्चा में भीलवाड़ा की मांडलगढ़ पंचायत 3. ट्रिपल R सेंटर "शक्ति संगम" 4. राजस्थान में संचालित 'एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल' 5. राजस्थान का पहला नेट ज़ीरो कूलिंग स्टेशन 6. FIH से मान्यता प्राप्त उत्तर भारत का पहला हॉकी टर्फ ग्राउण्ड 7. बिज-मैज 2026 8. नवगठित 8 जिलों में SC/ST सेल और एंटी ह्यूमन ट्रेफिकिंग यूनिट्स का गठन
5.	सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट (CGTMSE)
6.	भगवान बुद्ध के तथागत पवित्र अवशेष
7.	ट्विस्टर्स
8.	दलहन में आत्मनिर्भरता मिशन
9.	राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस
10.	नमस्ते योजना
11.	मलक्का जलडमरूमध्य
12.	भारत और मिस्र: द्विपक्षीय रक्षा सहयोग
13.	भारत ने जापान द्वारा रक्षा निर्यात प्रतिबंधों में ढील देने का स्वागत किया
14.	संयुक्त राष्ट्र एशिया और प्रशांत आर्थिक एवं सामाजिक आयोग (UN-ESCAP)
15.	भारत का आर्थिक और बीमा बाजार परिदृश्य 2026-2030 रिपोर्ट



राजस्थान परिदृश्य



राज उन्नति की चतुर्थ बैठक : जयपुर



चर्चा में क्यों?

- मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने 24 अप्रैल, 2026 को जयपुर में 'राज उन्नति' की चौथी बैठक की अध्यक्षता की।



मुख्य बिन्दु:

- 'राज उन्नति' (Raj-Unnati) राजस्थान सरकार की एक महत्वाकांक्षी पहल है, जिसे केंद्र सरकार के 'प्रगति' (PRAGATI) मॉडल की तर्ज पर विकसित किया गया है।

--2--

Daily Current Affairs

Date : 25 April, 2026



- यह सूचना और संचार प्रौद्योगिकी (ICT) पर आधारित एक बहुआयामी मंच है, जहाँ मुख्यमंत्री स्वयं वरिष्ठ अधिकारियों और जिला कलेक्टरों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा करते हैं।
- राजस्थान इस मॉडल को अपनाने वाला देश का पहला राज्य है।
- 17 जनवरी, 2026 को मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में जयपुर में 'राज उन्नति' की प्रथम बैठक आयोजित की गई थी।

अन्य महत्वपूर्ण बिन्दु:

- PM-PRAGATI (Pro-Active Governance And Timely Implementation) को वर्ष 2015 में केंद्र सरकार ने शुरू किया था, ताकि परियोजनाओं, योजनाओं और जन शिकायतों को टेक्नोलॉजी-आधारित मॉनिटरिंग और समयबद्ध समाधान के साथ लागू किया जा सके।
- **त्रि-स्तरीय प्रणाली** : इसमें सेवा तीर्थ (PMO), केंद्र सरकार के सचिव और राज्यों के मुख्य सचिव एक साथ एक प्लेटफॉर्म पर जुड़ते हैं।

--3--

राजस्थान में कॉपियों की AI आधारित जाँच

चर्चा में क्यों?

- हाल ही में, राजस्थान शिक्षा विभाग द्वारा जोधपुर जिले से सरकारी स्कूलों में विद्यार्थियों की कॉपियाँ जाँचने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) आधारित एक नई पहल की शुरुआत की गई।

AI Based Checking of Copies in Rajasthan



मुख्य बिन्दु:

- इस प्रोजेक्ट को 'राजस्थान के शिक्षा में बढ़ते कदम' के तहत संचालित किया जा रहा है।
- पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर शुरू की गई इस पहल के तहत स्कैन की गई कॉपियों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) आधारित सॉफ्टवेयर पर अपलोड किया जाता है।

Daily Current Affairs

Date : 25 April, 2026



- शिक्षा विभाग द्वारा वडोदरा की कंपनी एडऑप्टिमाइज सॉल्युशन और सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड (CEL) के सहयोग से मोबाइल AI एप को विकसित किया गया।
- **नोट :** सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड (CEL) भारत सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत एक प्रमुख सार्वजनिक क्षेत्र का उद्यम (PSU) है।
- प्रोजेक्ट लागू होने के बाद बच्चों और अभिभावकों को परीक्षा कॉपी की डिटेल्ड रिपोर्ट प्रेषित की जाएगी।

फैक्ट्स फॉर प्रीलिम्स:

- **राजस्थान के शिक्षा में बढ़ते कदम :** 11 जुलाई, 2022 को तत्कालीन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राज्य के स्कूली छात्रों को कोरोना काल में हुए पढ़ाई के नुकसान की भरपाई करने के लिये रेमेडिएशन कार्यक्रम 'राजस्थान के शिक्षा में बढ़ते कदम' का शुभारंभ किया।

UTKARSH

CIVIL
SERVICES

--:5:--

IIT जोधपुर द्वारा विकसित स्मार्ट 'थेरानोस्टिक' प्लेटफॉर्म

चर्चा में क्यों?

- हाल ही में, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (IIT), जोधपुर के वैज्ञानिकों ने सटीक स्वास्थ्य सेवा के लिए निदान और उपचार को मिलाकर स्मार्ट 'थेरानोस्टिक' प्लेटफॉर्म विकसित किया।



मुख्य बिन्दु:

- 'थेरानोस्टिक्स' शब्द 'थेरेपी' (उपचार) और 'डायग्नोस्टिक' (निदान) से मिलकर बना है। यह प्लेटफॉर्म एक ही समय में बीमारी की पहचान करने और उसका सटीक इलाज करने में सक्षम है।

--6--

Daily Current Affairs

Date : 25 April, 2026



- शोधकर्ताओं ने कैंसर और अन्य जटिल बीमारियों के लिए अल्ट्रा-स्मॉल नैनोमटेरियल्स (जैसे MXenes, मेटल-ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क और ब्लैक फॉस्फोरस) का उपयोग किया है। ये इतने छोटे होते हैं कि नग्न आंखों से दिखाई नहीं देते, लेकिन शरीर के अंदर सीधे रोगग्रस्त कोशिकाओं तक पहुंच सकते हैं।
- प्रकृति से प्रेरणा लेते हुए, यह टीम बायोमिमेटिक नैनोकैरियर्स भी विकसित कर रही है।
- इस अनुसंधान का एक प्रमुख आकर्षण 'फोटोथेरानोस्टिक्स' है, जिसमें बीमारियों के निदान, उपचार और निगरानी के लिए प्रकाश और नैनो-तकनीक के बीच की अंतर्क्रिया का उपयोग किया जाता है।
- इसमें नियर-इंफ्रारेड (NIR) प्रकाश का उपयोग किया जाता है, जो शरीर के ऊतकों में गहराई तक जाकर कैंसर कोशिकाओं को गर्मी या ऑक्सीजन रेडिकल्स के जरिए नष्ट कर देता है।

UTKARSH

CIVIL
SERVICES

--7--

✂ न्यूज़ इन शॉर्ट्स ⚡

क्र. सं.	न्यूज़
1.	<p>अखिल भारतीय शूटिंगबॉल प्रतियोगिता - 2026</p> <ul style="list-style-type: none">■ आयोजन : अलवर स्थित मुंशी बाग मैदान।■ अवधि : 24 से 26 अप्रैल, 2026 तक।
2.	<p>चर्चा में भीलवाड़ा की मांडलगढ़ पंचायत</p> <ul style="list-style-type: none">■ हाल ही में, केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सी.आर. पाटिल ने जल जीवन मिशन (JJM) की प्रगति की समीक्षा के लिए देशभर की चुनिंदा पंचायतों के प्रतिनिधियों से संवाद किया, जिसमें भीलवाड़ा जिले की मांडलगढ़ पंचायत की पेयजल व्यवस्था की सराहना की गई।
3.	<p>ट्रिपल R सेंटर "शक्ति संगम"</p> <ul style="list-style-type: none">■ जयपुर जिला परिषद द्वारा 'शक्ति संगम' नाम से एक अभिनव ट्रिपल आर (RRR - Reduce, Reuse, Recycle) सेंटर की स्थापना की गई।■ यह केंद्र मुख्य रूप से महिला सशक्तिकरण और स्वच्छता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से शुरू किया गया है।
4.	<p>राजस्थान में संचालित 'एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल'</p> <ul style="list-style-type: none">■ वर्तमान में राजस्थान स्टेट एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल सोसायटी द्वारा राज्य में 31 एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूलों (EMRS) का संचालन किया जा रहा है।■ 31वाँ और नवीनतम EMRS : जमवारामगढ़ (जयपुर) में जून, 2025 में प्रारंभ।■ राज्य में सभी EMRS विद्यालयों में 6 से 12 तक कक्षाएँ (CBSE से संबद्ध) संचालित होती हैं। कक्षा 11 एवं 12 में विज्ञान और कला संकाय उपलब्ध हैं।

5.	<p>राजस्थान का पहला नेट ज़ीरो कूलिंग स्टेशन</p> <ul style="list-style-type: none">हाल ही में, जयपुर में जयपुर नगर निगम और महिला हाउसिंग ट्रस्ट द्वारा संयुक्त रूप से राजस्थान का पहला नेट ज़ीरो कूलिंग स्टेशन (NZCS) स्थापित किया गया।इसका मुख्य उद्देश्य शहर के उन लोगों को भीषण गर्मी से राहत देना है, जो दिनभर बाहर काम करते हैं। जैसे - स्ट्रीट वेंडर्स, डिलीवरी पार्टनर्स और ड्राइवर।
6.	<p>FIH से मान्यता प्राप्त उत्तर भारत का पहला हॉकी टर्फ ग्राउण्ड</p> <ul style="list-style-type: none">भीलवाड़ा के फूलिया कलाँ में अंतरराष्ट्रीय हॉकी महासंघ (FIH) द्वारा मान्यता प्राप्त उत्तर भारत का पहला और एकमात्र हॉकी टर्फ ग्राउण्ड स्थित है।इसका निर्माण गाँव के भामाशाह सत्यनारायण लड्डा द्वारा करवाया गया।
7.	<p>बिज-मैज 2026</p> <ul style="list-style-type: none">हाल ही में, जगन्नाथ विश्वविद्यालय, जयपुर द्वारा राजस्थान सेंटर ऑफ एडवांस्ड टेक्नोलॉजी (R-CAT) के सहयोग से AI और डिजिटल बदलाव पर दो दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी 'बिज-मैज 2026' का आयोजन किया गया।
8.	<p>नवगठित 8 जिलों में SC/ST सेल और एंटी ह्यूमन ट्रेफिकिंग यूनिट्स का गठन</p> <ul style="list-style-type: none">हाल ही में, राज्य सरकार द्वारा 8 नए जिलों में कानून-व्यवस्था को मजबूत करने के लिए SC/ST (अनुसूचित जाति/जनजाति) सेल और एंटी ह्यूमन ट्रेफिकिंग यूनिट्स (AHTUs) के गठन को मंजूरी दी गई।वर्ष 2026-27 के बजट प्रावधानों के तहत गठित इन निकायों का उद्देश्य वंचित वर्गों के अधिकारों की रक्षा और मानव तस्करी जैसे संगठित अपराधों पर प्रभावी नियंत्रण पाना है।चयनित जिले : ब्यावर, डीडवाना-कुचामन, डीग, कोटपूतली-बहरोड़, बालोतरा, सलूंबर, फलोदी और खैरथल-तिजारा।

राष्ट्रीय परिदृश्य

सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट (CGTMSE)

चर्चा में क्यों?

- हाल ही में CGTMSE ने क्रेडिट गारंटी पर एक वैश्विक संगोष्ठी का आयोजन किया।



मुख्य बिन्दु:

CGTMSE:

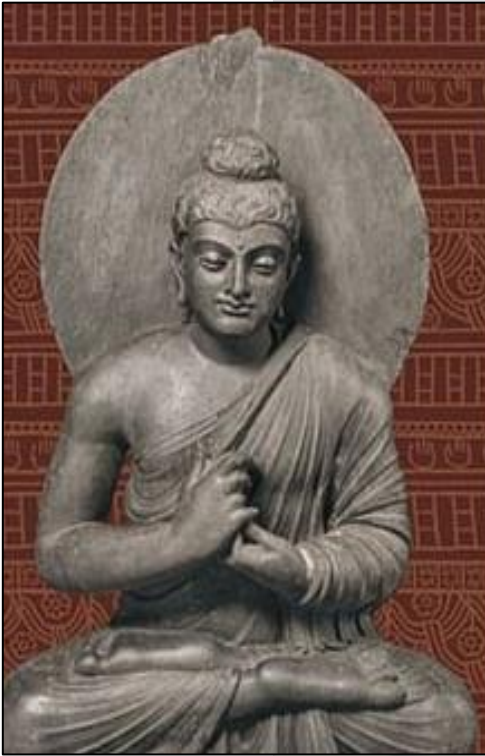
- स्थापना:** वर्ष 2000 में
- मंत्रालय:** इसे केंद्रीय सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय तथा भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (SIDBI) द्वारा संयुक्त रूप से स्थापित किया गया है।
- लक्ष्य:** इसका लक्ष्य सूक्ष्म एवं लघु उद्यम क्षेत्र के मौजूदा और नए उद्यमों को गारंटी प्रदान करते हुए कोलेटरल-फ्री औपचारिक ऋण की उपलब्धता बढ़ाना है।
- कार्यप्रणाली:** यदि कोई बैंक सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों को कोलेटरल-फ्री ऋण देता है और ऋणी डिफॉल्ट करता है, तो CGTMSE उस हानि का 75-90% हिस्सा वहन करता है।
- कार्य:** यह सूक्ष्म एवं लघु उद्यम क्षेत्र के लिए क्रेडिट गारंटी योजना का संचालन करता है।

इतिहास एवं संस्कृति

भगवान बुद्ध के तथागत पवित्र अवशेष

चर्चा में क्यों?

- भगवान बुद्ध के तथागत पवित्र अवशेषों की प्रदर्शनी लद्दाख में आयोजित की जाएगी।



मुख्य बिन्दु:

तथागत अवशेष:

- तथागत के पवित्र अवशेष बुद्ध के भौतिक अवशेषों (जैसे अस्थियाँ) और उनसे जुड़े स्मारकों का प्रतीक होते हैं। ये अवशेष श्रद्धा और सम्मान को दर्शाते हैं तथा इन्हें संघर्ष और नुकसान से सुरक्षित रखने पर विशेष जोर दिया जाता है।
- तथागत वह नाम है जिसका उपयोग ऐतिहासिक बुद्ध शाक्यमुनि ने स्वयं को संदर्भित करने के लिए किया था। इसका विवरण पालि त्रिपिटक में प्राप्त होता है।

Daily Current Affairs

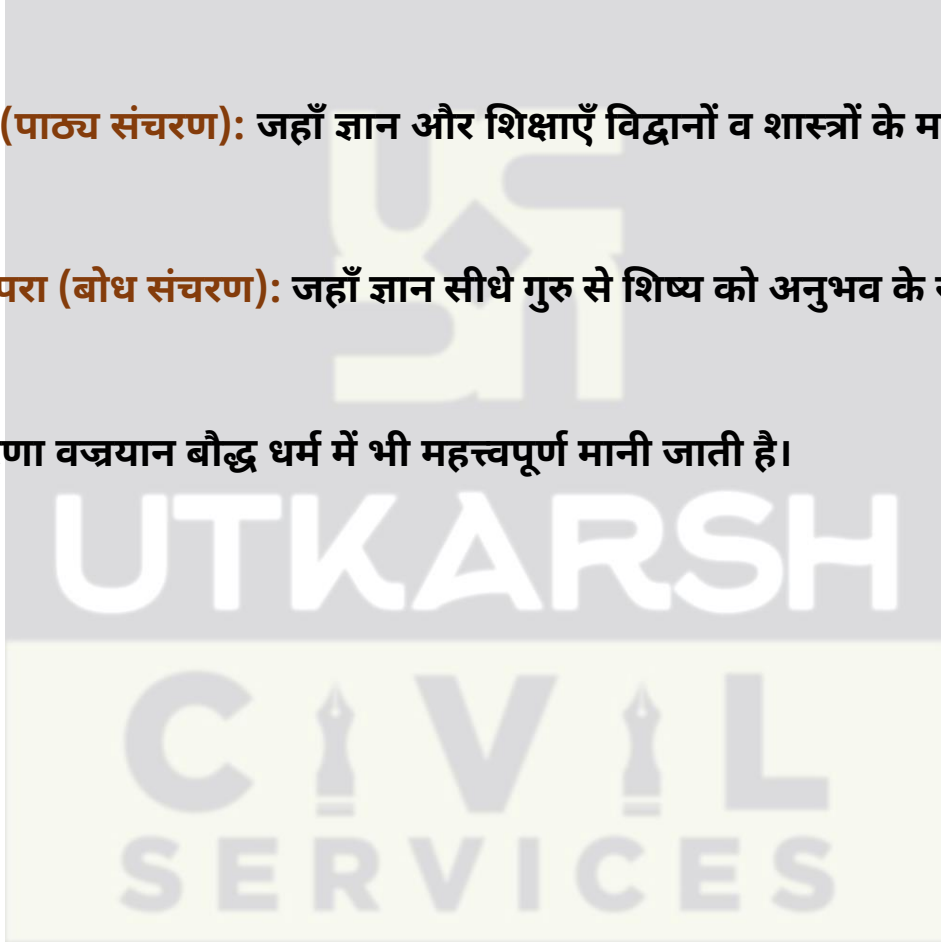
Date : 25 April, 2026



- तथागत का अर्थ है: वह जो (यथार्थ को जानकर) वैसा ही आया और चला गया" है। यह उस व्यक्ति को दर्शाता है जो सत्य के मार्ग पर चलकर निर्वाण प्राप्त कर चुका है और जो कहता है, वही अमल में लाता है।

महायान बौद्ध परंपरा में यह शब्द दो प्रकार की परंपराओं (वंशावली) को समझने में मदद करता है:

- ग्रंथ परंपरा (पाठ्य संचरण): जहाँ ज्ञान और शिक्षाएँ विद्वानों व शास्त्रों के माध्यम से आगे बढ़ती हैं।
- अनुभव परंपरा (बोध संचरण): जहाँ ज्ञान सीधे गुरु से शिष्य को अनुभव के रूप में मिलता है।
- यह अवधारणा वज्रयान बौद्ध धर्म में भी महत्त्वपूर्ण मानी जाती है।



-:12:-

भूगोल एवं भू-विज्ञान

ट्विस्टर्स



चर्चा में क्यों?

- अमेरिका में 'ट्विस्टर्स' नामक प्रबल मौसम परिघटना देखी गई है।



मुख्य बिन्दु:

ट्विस्टर्स:

- यह टॉरनेडो का दूसरा नाम है। यह बहुत तेज़ घूमने वाली हवा का स्तंभ होता है (लगभग 500 किमी/घंटा), जो तड़ितझंझा वाले बादल से जमीन तक फैलता है।
- **निर्माण:** जब गर्म और नम हवा, ठंडी और शुष्क हवा से टकराती है, तो वायुमंडल में अस्थिरता पैदा होती है और तड़ितझंझा के भीतर ऊपर उठने वाली प्रबल हवाएँ बनती हैं।
- हवा की दिशा और गति में बदलाव से हवा घूमने लगती है। जब यह घूर्णन लंबवत होकर तेज हो जाता है, तब टॉरनेडो या ट्विस्टर बनता है।
- अमेरिका के "टॉरनेडो एली" (टेक्सास, ओक्लाहोमा, कंसास, नेब्रास्का) नामक क्षेत्र में सर्वाधिक संख्या में टॉरनेडो आते हैं।

आर्थिक घटनाक्रम

दलहन में आत्मनिर्भरता मिशन

चर्चा में क्यों?

- दलहन में आत्मनिर्भरता मिशन के तहत बिहार की पहली व्यवस्थित दलहन खरीद पहल शुरू की गई है।



मुख्य बिन्दु:

दलहन में आत्मनिर्भरता मिशन:

- उद्देश्य:** इसका उद्देश्य घरेलू उत्पादन को बढ़ाकर और आयात पर निर्भरता कम करके दलहन में आत्मनिर्भरता प्राप्त करना है। इसके साथ ही, यह किसानों की आय में सतत सुधार सुनिश्चित करता है।
- लक्ष्य:** वर्ष 2030-31 तक घरेलू दलहन उत्पादन को बढ़ाकर 350 लाख टन करना है। साथ ही, दलहन रकबा क्षेत्र को बढ़ाकर 310 लाख हेक्टेयर करना है।
- शुरुआत:** इसकी घोषणा केंद्रीय बजट 2025-26 में की गई थी और इसे 1 अक्टूबर, 2025 को मंजूरी दी गई थी।
- योजना-अवधि:** 6 वर्ष (2025-26 से 2030-31)
- मंत्रालय:** केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय।
- मुख्य फसलें:** तुअर/अरहर; उड़द और मसूर।

भारतीय शासन एवं राजव्यवस्था

राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस

चर्चा में क्यों?

- पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना के उपलक्ष्य में प्रत्येक वर्ष 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया जाता है।



मुख्य बिन्दु:

- यह दिन 73वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम, 1992 की याद में मनाया जाता है, जो 1993 में लागू हुआ और पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया।

पंचायती राज व्यवस्था की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

- स्वतंत्रता के बाद, बलवंत राय मेहता समिति (1957) के माध्यम से विकेंद्रीकृत शासन को बढ़ावा दिया गया, जिसने तीन स्तरीय पंचायती राज प्रणाली की सिफारिश की, जिसे पहली बार 1959 में राजस्थान में लागू किया गया था।

- संविधान में 73वें संशोधन अधिनियम के माध्यम से संवैधानिक समर्थन प्राप्त हुआ, जिसने पंचायती राज व्यवस्था को अनिवार्य बना दिया और उन्हें संविधान के भाग IX (अनुच्छेद 243-243O) में शामिल कर दिया।

पंचायती राज संस्थाओं की संरचना

- पंचायती राज व्यवस्था विकेंद्रीकरण के सिद्धांत पर आधारित है। सत्ता केंद्र और राज्य सरकारों से ग्राम स्तर पर निर्वाचित प्रतिनिधियों को हस्तांतरित की जाती है।
- पंचायती राज व्यवस्था की संरचना तीन स्तर की होती है:
 - ग्राम पंचायत (गांव स्तर): जल आपूर्ति, स्वच्छता, स्ट्रीट लाइटिंग और ग्राम अवसंरचना जैसे बुनियादी स्थानीय प्रशासन का प्रबंधन करती है।
 - ब्लॉक पंचायत (मध्यवर्ती स्तर) : गांवों में विकास का समन्वय करती है और सरकारी योजनाओं के उचित कार्यान्वयन को सुनिश्चित करती है।
 - जिला पंचायत (जिला स्तर): योजना और संसाधन आवंटन पर ध्यान केंद्रित करते हुए, ब्लॉकों में विकास गतिविधियों की देखरेख और समन्वय करती है।

पंचायती राज व्यवस्था को सुदृढ़ करने की पहल

- स्वामित्व योजना: 24 अप्रैल, 2021 को शुरू की गई इस योजना का उद्देश्य ड्रोन और जीआईएस तकनीक का उपयोग करके आबाद ग्रामीण क्षेत्रों का मानचित्रण करके और संपत्ति कार्ड जारी करके ग्रामीण परिवारों को कानूनी स्वामित्व अधिकार प्रदान करना है।
- सभासार: एआई-संचालित बैठक दस्तावेज़ीकरण: सभासार एक एआई-आधारित उपकरण है जो स्वचालित रूप से ग्राम सभा की बैठकों के मिनट तैयार करता है, मैनुअल कार्यभार को कम करता है और निगरानी को मजबूत करता है।
- ईग्रामस्वराज - पंचायतों के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म: ईग्रामस्वराज एक उपयोगकर्ता-अनुकूल वेब पोर्टल है जो पंचायतों में योजना, प्रगति रिपोर्टिंग, वित्तीय प्रबंधन और परिसंपत्तियों की निगरानी में पारदर्शिता बढ़ाता है। यह सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (पीएफएमएस) से जुड़ा हुआ है, जो केंद्रीय वित्त आयोग के फंड को राज्यों से पंचायती राज संस्थानों में ऑनलाइन ट्रांसफर करने की सुविधा देता है।

Daily Current Affairs

Date : 25 April, 2026



- **ग्राम ऊर्जा स्वराज:** ई-ग्रामस्वराज के अंतर्गत ग्राम ऊर्जा स्वराज एक डिजिटल डैशबोर्ड है जो ग्राम पंचायत स्तर पर नवीकरणीय ऊर्जा संपत्तियों को वास्तविक समय में ट्रैक करता है।
- **मेरी पंचायत:** मेरी पंचायत ऐप एक एकीकृत एम-गवर्नेंस प्लेटफॉर्म है जिसे राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र द्वारा डिजाइन और विकसित किया गया है।
- इसका उद्देश्य पंचायत मामलों में बेहतर शासन, जवाबदेही और नागरिक भागीदारी में सुधार करके ग्रामीण समुदायों को सशक्त बनाना है।
- राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान केंद्र प्रायोजित योजना है जिसका उद्देश्य क्षमता निर्माण, संस्थागत विकास और अवसंरचनात्मक सहायता के माध्यम से पंचायती राज संस्थाओं को मजबूत करना है।
- महिला-हितैषी ग्राम पंचायत एक संस्थागत पहल है जिसका उद्देश्य स्थानीय शासन में महिलाओं के नेतृत्व को मजबूत करना है।
- सरकार ने निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों (ईडब्ल्यूआर) के नेतृत्व, संचार और निर्णय लेने के कौशल को बढ़ाने के लिए "सशक्त पंचायत-नेत्री अभियान" शुरू किया है।
- मॉडल यूथ ग्राम सभा (MYGS) जमीनी स्तर पर लोकतंत्र में युवाओं को शामिल करने के उद्देश्य से शुरू की गई एक पहल है। स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग तथा जनजातीय मामलों के मंत्रालय के सहयोग से कार्यान्वित इस पहल में जवाहर नवोदय विद्यालयों और एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों के कक्षा 9 और 10 के छात्र भाग लेते हैं।
- पंचायत (अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तार) अधिनियम, 1996 (पीईएसए अधिनियम) के प्रावधान: पीईएसए अधिनियम, 1996 पंचायती राज प्रावधानों को अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तारित करता है, जिससे 10 राज्यों के आदिवासी क्षेत्रों में ग्राम सभा के नेतृत्व वाली शासन व्यवस्था मजबूत होती है।
- यह अधिनियम आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, राजस्थान, तेलंगाना और हिमाचल प्रदेश जैसे राज्यों में पांचवीं अनुसूची के क्षेत्रों पर लागू होता है, जिनमें से अधिकांश राज्यों ने ओडिशा को छोड़कर पीईएसए नियमों को अधिसूचित कर दिया है।

-:17:-



उत्कर्ष® Jodhpur : JALORI GATE CIRCLE, JODHPUR | Support@utkarsh.com | Call us at : 9829 213 213
Jaipur : NEAR MAHESH NAGAR THANA, GOPALPURA BYPASS ROAD, JAIPUR

प्रगति

- सार्वजनिक क्षेत्र की संस्थाओं में तेजी से डिजिटल परिवर्तन हो रहा है, जिससे जमीनी स्तर पर पारदर्शिता, दक्षता और जवाबदेही में वृद्धि हुई है।
- अब 95% से अधिक गांवों में 3G/4G कनेक्टिविटी उपलब्ध होने के साथ, अंतिम-मील सेवा वितरण में काफी सुधार हुआ है।
- 65 लाख से अधिक ग्राम स्तरीय उद्यमियों द्वारा संचालित साझा सेवा केंद्र ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल सेवाओं को आसानी से सुलभ बना रहे हैं।
- इसके अतिरिक्त, लगभग 2.18 लाख ग्राम पंचायतों में से लगभग 2.14 लाख पहले से ही कनेक्टेड और सेवा-तैयार हैं, जो ग्राम स्तर पर डिजिटल समावेशन में मजबूत प्रगति को दर्शाता है।

पीआरआई के सामने चुनौतियाँ

- **राजकोषीय निर्भरता:** पंचायती राज संस्थाओं की अपनी आय के न्यूनतम स्रोतों के कारण राज्य और केंद्र सरकार से मिलने वाले अनुदान पर अत्यधिक निर्भरता होती है।
- **क्षमता की कमी :** प्रशिक्षित कर्मियों, योजना बनाने की विशेषज्ञता और डिजिटल साक्षरता की कमी से कार्यान्वयन की गुणवत्ता कमजोर हो जाती है।
- **राज्य स्तर पर प्रतिरोध:** कई राज्य सरकारें नौकरशाही नियंत्रण के माध्यम से पीआरआई की स्वायत्तता को कम करती हैं।
- **अभिजात वर्ग का कब्जा:** जातिगत पदानुक्रम, लैंगिक पूर्वाग्रह और स्थानीय सत्ता संरचनाएं संवैधानिक आरक्षणों के बावजूद प्रतिनिधित्व को विकृत करती हैं।
- **कमजोर जवाबदेही:** अपर्याप्त लेखापरीक्षा तंत्र और सामाजिक लेखापरीक्षा की कम पहुंच से खामियां लीक हो जाती हैं और पारदर्शिता कम हो जाती है।

योजनाएँ एवं नीतियाँ

नमस्ते योजना

चर्चा में क्यों?

- 'नेशनल एक्शन फॉर मैकेनाइज्ड सैनिटेशन इकोसिस्टम' (NAMASTE) योजना ने लगभग 90 हजार सीवर और सेप्टिक टैंक श्रमिकों की पहचान करके एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है।



मुख्य बिन्दु:

नमस्ते योजना:

- **शुरुआत:** इसे 2023 में केंद्रीय क्षेत्रक योजना के रूप में शुरू किया गया था।
- **उद्देश्य:** इसका उद्देश्य खतरनाक सीवर और सेप्टिक टैंकों की सफाई में लगे व्यक्तियों को औपचारिक रोजगार प्रदान करना और उनके पुनर्वास की दिशा में कार्य करना है।
- **संयुक्त पहल:** यह केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय तथा केंद्रीय आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा संयुक्त रूप से शुरू की गई है।
- इसे राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त और विकास निगम (NSKFDC) द्वारा कार्यान्वित किया जाता है।
- **लक्षित समूह:** सीवर और सेप्टिक टैंक स्वच्छता श्रमिक (SSWs); 2024 में इसमें कचरा बीनने वालों को भी शामिल किया गया है।

--:19::--



अंतरराष्ट्रीय परिदृश्य



मलक्का जलडमरूमध्य



चर्चा में क्यों?

- होर्मुज संकट ने विश्व के एक अन्य सबसे बड़े चोकपॉइंट, मलक्का जलडमरूमध्य की ओर ध्यान आकर्षित किया है।



मुख्य बिन्दु:

- मलक्का जलडमरूमध्य:



- अवस्थिति: यह अंडमान सागर (हिंद महासागर) और दक्षिण चीन सागर (प्रशांत महासागर) को जोड़ने वाला जलमार्ग है।

--:20:--

Daily Current Affairs

Date : 25 April, 2026



- **तटवर्ती देश:** इंडोनेशिया, थाईलैंड, मलेशिया और सिंगापुर।

सामरिक महत्त्व:

- विश्व के लगभग 22% समुद्री व्यापार इसी होकर गुजरते हैं।
- इसे सबसे बड़ा "तेल पारगमन चोकपॉइंट" माना जाता है।
- यह पूर्वी एशिया से मध्य पूर्व और यूरोप तक का सबसे छोटा समुद्री मार्ग है।

चिंताएँ:

- इसका सबसे संकरा बिंदु (सिंगापुर जलडमरूमध्य का फिलिप्स चैनल) एक प्राकृतिक अवरोध उत्पन्न करता है। इससे जहाजों के टकराने या तेल रिसाव की चिंताएं बनी रहती हैं।
- इसके कुछ हिस्से अपेक्षाकृत उथले हैं, जो बड़े जहाजों के आवागमन को बाधित करते हैं।
- व्यापारिक जहाजों पर समुद्री डकैती और हमलों का खतरा बना रहता है।

--:21:--

भारत और मिस्र: द्विपक्षीय रक्षा सहयोग

चर्चा में क्यों?

- हाल ही में, काहिरा में भारत-मिस्र संयुक्त रक्षा समिति (जेडीसी) की 11वीं बैठक आयोजित की गई। इसने सामरिक साझेदारी (2023) और रक्षा सहयोग पर समझौता ज्ञापन (2022) के तहत द्विपक्षीय रक्षा संबंधों को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया।





मुख्य बिन्दु:

- **संबंधों की वर्तमान स्थिति**
- **राजनीतिक और रणनीतिक:** रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक उन्नत (2023)।
- **नियमित उच्च स्तरीय दौरे;** मिस्र को मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया (गणतंत्र दिवस 2023)
- **बहुपक्षीय मंचों में सहयोग (संयुक्त राष्ट्र, ब्रिक्स विस्तार)।**
- **आर्थिक संबंध:** द्विपक्षीय व्यापार लगभग 6-7 अरब डॉलर का है।
- **समुद्री और भूराज्य महत्त्व:** स्वेज नहर पर मिस्र का नियंत्रण, जो भारत के व्यापार के लिए महत्त्वपूर्ण है; हिंद महासागर और भूमध्यसागर की कनेक्टिविटी में अभिसरण; और हिंद महासागर क्षेत्र (आईओआर) में एक प्रमुख सुरक्षा प्रदाता के रूप में भारत की भूमिका।
- **रक्षा सहयोग:** संस्थागत तंत्र: संयुक्त रक्षा समिति (जेडीसी)। प्रमुख फोकस क्षेत्रों में संयुक्त अभ्यास और प्रशिक्षण; रक्षा उत्पादन और प्रौद्योगिकी; और समुद्री सुरक्षा सहयोग शामिल हैं।
- **एक्सरसाइज साइक्लोन (सेना अभ्यास) भारतीय सेना (पैरा स्पेशल फोर्स) और मिस्र की स्पेशल फोर्स के बीच एक संयुक्त विशेष बल अभ्यास है।**
- **11वीं संयुक्त रक्षा समिति (जेडीसी) के प्रमुख परिणाम**
- **भविष्योन्मुखी रक्षा रोडमैप (2026-27):** दोनों देशों ने एक संरचित रक्षा सहयोग योजना पर सहमति व्यक्त की, जो निम्नलिखित बिंदुओं पर केंद्रित है:
 - सैन्य-से-सैन्य संपर्कों का विस्तार
 - संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यासों को तीव्र करना
 - समुद्री सुरक्षा सहयोग को बढ़ावा देना
 - सैन्य अभ्यासों का बढ़ता पैमाना और जटिलता
 - रक्षा उत्पादन और प्रौद्योगिकी सहयोग को मजबूत करना

Daily Current Affairs

Date : 25 April, 2026



- **रक्षा उद्योग सहयोग:** भारत ने अपने रक्षा विनिर्माण विकास को उजागर किया, जिसमें 20 अरब डॉलर से अधिक का उत्पादन और 100 से अधिक देशों को लगभग 4 अरब डॉलर का निर्यात शामिल है।
- रक्षा उद्योग सहयोग योजना विकसित करने के लिए समझौता
- प्रमुख क्षेत्रों में सह-विकास और सह-उत्पादन, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण और औद्योगिक साझेदारी शामिल हैं।
- यह रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर भारत और निर्यात आधारित विकास के लिए भारत के प्रयासों को दर्शाता है।
- **समुद्री सुरक्षा सहयोग:** नौसेना-से-नौसेना स्टाफ वार्ता का पहला आयोजन हुआ, जिसमें भारत ने नौवहन की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने में भारतीय नौसेना की भूमिका और सूचना संलयन केंद्र-हिंद महासागर क्षेत्र के योगदान पर जोर दिया।
- समुद्री सहयोग हिंद महासागर और उससे परे भारत की रणनीतिक पहुंच का केंद्र बिंदु है, विशेष रूप से समुद्री संचार मार्गों को सुरक्षित करने और उभरते खतरों का मुकाबला करने में।
- यह क्षेत्र में सभी के लिए सुरक्षा और विकास (सागर) के भारत के दृष्टिकोण के अनुरूप है।
- **वायु सेना सहयोग:** मिस्र के वायु सेना कमांडर के साथ बैठक हुई और वायु-से-वायु सहयोग में हो रही वृद्धि को मान्यता दी गई। संयुक्त अभ्यास और प्रशिक्षण आदान-प्रदान की संभावनाएं मौजूद हैं।

--:24:--

भारत ने जापान द्वारा रक्षा निर्यात प्रतिबंधों में ढील देने का स्वागत किया

चर्चा में क्यों?

- जापान द्वारा अपने हथियार निर्यात पर लगे प्रतिबंधों में ढील देने के बाद, भारत ने इस कदम का स्वागत किया और कहा कि दोनों पक्षों ने "अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा के हित में व्यावहारिक सहयोग बढ़ाने" के लिए प्रतिबद्धता जताई है।



मुख्य बिन्दु:

- पहले के प्रतिबंधों के तहत हथियारों का निर्यात केवल पांच श्रेणियों तक सीमित था - बचाव, परिवहन, चेतावनी, निगरानी और बारूदी सुरंगों को साफ करना।

Daily Current Affairs

Date : 25 April, 2026



- इसका मतलब यह है कि जापान अब उन 17 देशों को घातक हथियार बेच सकता है जिनके साथ उसके रक्षा समझौते हैं, जिनमें अमेरिका और ब्रिटेन भी शामिल हैं।
- चल रही समीक्षा का उद्देश्य सख्त लेकिन अधिक लचीली शर्तों के तहत स्थानांतरण की अनुमति देना है, विशेष रूप से विश्वसनीय भागीदारों के लिए।
- भारत और जापान रणनीतिक रक्षा और सुरक्षा परिदृश्य में द्विपक्षीय और बहुपक्षीय रूप से सहयोग करते हैं, जिसमें क्वाड समूह भी शामिल है।

महत्त्व:

- यह ऐसे समय में महत्त्वपूर्ण हो जाता है जब भारत और जापान दोनों ही हिंद-प्रशांत क्षेत्र में आक्रामक चीन की चुनौती का सामना कर रहे हैं।
- इस बदलाव से रक्षा प्लेटफार्मों के सह-विकास, आपूर्ति श्रृंखला एकीकरण और प्रौद्योगिकी साझाकरण के लिए रास्ते खुलने की उम्मीद है, जो भारत के लिए बढ़ती रुचि के क्षेत्र हैं।

महत्त्वपूर्ण सूचकांक एवं रिपोर्ट

संयुक्त राष्ट्र एशिया और प्रशांत आर्थिक एवं सामाजिक आयोग (UN-ESCAP)

चर्चा में क्यों?

- UN-ESCAP द्वारा 'एशिया और प्रशांत का आर्थिक और सामाजिक सर्वेक्षण 2026' रिपोर्ट जारी की गई है।



मुख्य बिन्दु:

- अनुमान: इस वर्ष भारतीय अर्थव्यवस्था की संवृद्धि दर 6.4% (2025 में 7.4% के बाद) और 2027 में 6.6% रहने का अनुमान है।

--:27:--

UN-ESCAP

- **मुख्यालय:** बेंकॉक (थाईलैंड)
- यह एशिया-प्रशांत क्षेत्र में एक अंतर-सरकारी मंच है।
- **स्थापना:** इसकी स्थापना 1947 में एशिया और सुदूर पूर्व के लिए आर्थिक आयोग (ECAFE) के रूप में हुई थी।
- **मूल निकाय:** यह संयुक्त राष्ट्र के 5 क्षेत्रीय आयोगों में से एक है और आर्थिक और सामाजिक परिषद (ECOSOC) को रिपोर्ट करता है।
- **सदस्यता:** इसमें 53 सदस्य देश और 9 एसोसिएट सदस्य शामिल हैं।
- इसमें एशिया-प्रशांत क्षेत्र के बाहर के देश भी शामिल हैं। उदाहरण के लिए, UK और फ्रांस जैसे देश।
- भारत इसका संस्थापक सदस्य है।

भारत का आर्थिक और बीमा बाजार परिदृश्य 2026-2030 रिपोर्ट



चर्चा में क्यों?

- स्विस री (Swiss Re) ने 'भारत का आर्थिक और बीमा बाजार परिदृश्य 2026-2030' शीर्षक से रिपोर्ट जारी की।



मुख्य बिन्दु:

- इस रिपोर्ट में भारत के बीमा क्षेत्रक के तेजी से विस्तार का अनुमान लगाया गया है। इसके अनुसार 2026 से 2030 के बीच बीमा प्रीमियम संवृद्धि दर 6.9% तक पहुँच सकती है।

भारत में बीमा क्षेत्रक

- **विश्व में स्थान:** कुल प्रीमियम के मामले में भारत, विश्व का 10वां सबसे बड़ा बीमा बाजार है।

- **बीमा घनत्व:** यह प्रति व्यक्ति औसत प्रीमियम राशि है। वर्तमान में यह 97.0 अमेरिकी डॉलर है।

- **घरेलू वित्तीय परिसंपत्तियों में बीमा की हिस्सेदारी:** घरेलू वित्तीय परिसंपत्तियों में बीमा और पेंशन फंड की हिस्सेदारी वित्त वर्ष 2025 में बढ़कर 29.6% हो गई।

बीमा क्षेत्रक को मजबूत करने के लिए उठाए गए कदम

- **2047 तक सभी के लिए बीमा:** यह भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (IRDAI) का विजन है।

- **वर्ष 2025 में संशोधन:** बीमा क्षेत्रक में पूंजी और प्रौद्योगिकियों को आकर्षित करने के लिए 100% प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) की अनुमति दी गई।

- **GST से छूट:** व्यक्तिगत जीवन बीमा और स्वास्थ्य बीमा पर जीएसटी हटा दिया गया। इससे बीमा कराना वहनीय हो गया।

- **उपभोक्ताओं के हितों का संरक्षण:** स्वास्थ्य बीमा में मोरेटोरियम अवधि को घटाकर 5 वर्ष कर दिया गया है। इसका अर्थ है कि यदि कोई व्यक्ति लगातार 5 साल तक बिना रुकावट स्वास्थ्य बीमा कवर बनाए रखता है, तो उसके बाद बीमा कंपनी जानकारी छिपाने या गलत जानकारी देने के आधार पर उसके क्लेम को अस्वीकार नहीं कर सकती।